ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की एक उपयोजना के रूप में शुरू किया गया था तथा यह जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत भी जारी है। 1989–90 तक 10 लाख कुओं की योजना का उद्देश्य अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छोटे और सीमान्त किसानों तथा गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे मुक्त बंधुआ मजदूरों को सिंचाई के कुएं निःशुल्क उपलब्ध कराना था। 1990–91 के बाद से 10 लाख कुओं की योजना के अंतर्गत अनेक कार्यों का पैकेज जैसे खुले सिंचाई कुओं का निर्माण कार्य/लघु सिंचाई योजनायें जैसे सिंचाई टैंक, जल एकत्रीकरण ढांचे तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ग्रामीण गरीबों की भूमि के विकास का कार्य भी शामिल किया गया।

इस योजना के अंतर्गत व्यापक आबंटन और इस योजना के लाभ गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के गरीब परिवारों को दिलाने की मांग थी। तदनुसार वर्ष 1993–94 से गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छोटे तथा सीमान्त किसानों, जो गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे हैं, को कवर करने के लिए 10 लाख कुओं की योजना के कार्य क्षेत्र में विस्तार किया गया है। क्षेत्रगत निधि निर्धारण जो, 1992–93 तक जवाहर रोजगार योजना की कुल निधियों का 20% था, को इस शर्त के आधार पर कि जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले लाभ 10% से अधिक न हों, 1993–94 से बढ़ाकर 30% कर दिया गया है।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार वित्तीय वर्ष 1993–94 के अन्त तक 10 लाख कुंओं की योजना के अंतर्गत राज्य में 19621 कुएं निर्मित किए गए है।

मध्य प्रदेश में रोजगार आश्वासन योजना का कार्यान्वयन

1521. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा रोजगार आश्वासन योजना के अंतर्गत शामिल किए गए मध्य प्रदेश के गांवों/शहरों की जिलेवार संख्या कितनी-कितनी है और प्रत्येक गांव और शहर के लिए 1993–94 और 1994–95 के वर्ष के लिए प्रत्येक योजना-वार क्रमशः कितनी-कितनी धनराशि आबंटित की गई है ;

(ख) बेरोजगार युवकों से जिलेवार कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और उनमें आदिवासी आवेदकों की संख्या कितनी है और अब तक इस योजना से कितने बेरोजगार युवक लाभान्वित हुए हैं; और

(ग) इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिलेवार कितनी-कितनी धनराशि आबंटित की गई हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) सुनिश्चित रोजगार योजना 2 अक्तूबर, 1993 से उन खंडों के सभी गांवों में कार्यान्वित की जा रही है जहां पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली संचलन में है। मध्य प्रदेश में 223 खंडों के सभी गांवों में सुनिश्चित रोजगार योजना कार्यान्वित की जा रही है जो पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शामिल है। सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के लिए निधियां आबंटित की जाती हैं जहां श्रमिक कार्य के रोजगार की मांग है।

18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम आयु वर्ग के लोगों, जिन्हें रोजगार की जरूरत है, को स्वयं को उन ग्राम पंचायतों, जहां वे रहते हैं, पंजीकृत करवाना चाहिए। मध्य प्रदेश से प्राप्त अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार, सुनिश्चित रोजगार

योजना के अन्तर्गत 1010000 लोगों को पंजीकृत किया गया है और 30 जून, 1994 तक 86.81 लाख श्रम दिनों का रोजगार जुटाया गया है । सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत पंजीकृत लोगों के जिलावार ब्यौरे केन्द्र स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

1993–94 और 1994–95 (अभी तक) के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना के कार्यान्वयन हेतु मध्य प्रदेश के लिए क्रमश: 5695.00 लाख रुपए और 8920.00 लाख रुपए की केन्द्रीय सहायता रिलीज की गई थी। 1993–94 और 1994–95 के दौरान मध्य प्रदेश में सुनिश्चित रोजगार योजना के कार्यान्वयन हेतु निधियों की जिलावार रिलीज के ब्यौरे संलग्न विवरण में दर्शाये गए हैं । (**नीचे देखिए**) इन जिलों को निधियों की और रिलीज, इनके पास उपलब्ध निधियों के उपयोग के आधार पर की जाएगी ।

विवरण

1993–94 और 1994–95 के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश सरकार को केन्द्रीय निधियों की जिलावार रिलीज के ब्यौरे

क्रमांक	जिले का नाम	रिलीज की गई केन्द्रीय निधियां	
		1993–94 (लाख रु० में)	1994–95 (लाख रु० में)
1	2	3	4
1	झबुआ	360.00	480.00
2	झार	360.00	480.00
3	खारगांव	420.00	560.00
4	बस्तर	320.00	1280.00
5	सरगुजा	240.00	960.00
6	मांडला	480.00	640.00
7	सिधी	240.00	320.00
8	शाहडोल	360.00	480.00
9	रायगढ़	390.00	520.00
10	रायपुर	120.00	160.00
11	दुर्ग	120.00	160.00
12	राजनन्द गांव	180.00	240.00
13	बिलासपुर	360.00	480.00
14	बालाघाट	90.00	120.00
15	सिवनी	150.00	200.00
16	छिंदवाड़ा	330.00	440.00
17	जबलपुर	275.00	200.00
18	रतलाम	90.00	120.00
19	मुरैना	60.00	80.00
20	खण्डवा	120.00	160.00
21	देवास	90.00	120.00
22	बेतूल	300.00	400.00
23	होशंगाबाद	240.00	320.00
	कुल :	5695.00	8920.00

मध्य प्रदेश में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण

1522. **श्री दिलीप सिंह जूदेव :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत अब तक कितने किलो-मीटर सड़कों का निर्माण हुआ है और इन पर कितनी धनराशि खर्च की गई है ;

(ख) क्या सरकार मध्य प्रदेश में ग्रामीण सड़क परियोजनायें शुरू करने के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त योजना कब से शुरू होगी ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) :(क) मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 1993–94 तक राज्य में 9788.05 लाख रुपए के खर्च से 41696.91 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है।